terrorist and secessionist activities in Assam. 2649 ULFA and 33 Bodo activists have been apprehended in Assam and other affected regions in this Operation upto 22nd November, 1991. 671 weapons and a sum of Rs. 58.17 lakhs have also been recovered. 9 militants have died as a result of the operation by the Army. 42 ULFA detenues have been released in phases in exchange of hostages. 6 persons are still held captive by the ULFA militants. Since the Army is providing aid to the civil authority in Assam, the duration of operation will depend upon the State Government. The average daily expenditure on Army is Rs. 21 lakh (Twenty-one lakh) approximately.

गोल डाकखाना इत्यादि में यातायात संबंधी प्रबन्ध

560. **श्री विश्वास राव रामराव पाटिल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोल डाकखाना, पटेल चौक और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास के चौराहों में भारी यातायात के बावजूद न तो वहां यातायात पुलिस के किसी पुलिसमैन को तैनात किया जाता है और न ही किसी प्रकार के यातायात सिग्नल लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार वहां पर यातायात सिग्नल लगाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो सिग्नल व्यवस्था कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि गोल डाकखाना, पटेल चौक और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चौराहों पर भीड़-भाड़ के समय यातायात पुलिस कार्मिक तैनात किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त गोल डाकखाने पर 7.00 बजे प्रात: से 9.00 बजे प्रात: और 12.00 बजे से 2.00 बजे दोपहर उपिराहनतक यातायात पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए जाते हैं । इन चौराहों पर यातायात सिग्नल लगाना, सुचारू सड़क यातायात के लिए व्यवहारिक नहीं समझा गया ।

(ग) और (घ) इस समय ट्रैफिक सिग्नल लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कश्मीर समस्या के संबंध में सुझाव

561. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को कोआर्डिनेशन कमेटी आन कश्मीन नामक एक स्वयंसेवी संगठन से कश्मीन समस्या को सुलझाने के संबंध में एक फार्मूला प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त सुझावों के आधार पर क्या सरकार कश्मीरी उग्रवादियों के दलों से बातचीत करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) कश्मीर के बारे में समन्वयन समिति की ओर से एक अपील प्राप्त हुई है । जिसमें कश्मीर समस्या को हल करने के लिए समिति द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं ।

सरकार ने किसी से भी बात करने की अपनी इच्छा से अवत कराया है

परन्तु समस्या का हल भारत के संविधान के ढांचे के अन्तर्गत किया जाना है । प्रमुख आतंकवादी संगठनों ने अभी तक बातचीत के लिए रचनात्मक उत्तर नहीं दिया है।

तारीख 13-11-1991 को जम्मू और कश्मीर राज्य के राजनैतिक नेताओं तथा प्रमुख राजनैतिक व्यक्तियों की एक बैठक हुई। देश की एकता और अखंण्डता को उत्पन्न चुनौती का दृढ़ संकल्प से सामना करने के लिए लोगों द्वारा किए गए संकल्प को बैठक में दोहराया गया। बैठक में जम्मू और कश्मीर पुलिस सहित सुरक्षा बलों द्वारा राज्य में अत्यन्त कठिन और दुर्गम परिस्थितियों में आतंकवाद का सामना करने के लिए उनकी प्रशंसा की गई तथा सुरक्षा बलों के उस सभी सदस्यों के परिवारों प्रशासन तथा उन नागरिकों के प्रति शोक व्यक्त किया गया जिन्होंने इस संघर्ष में अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया ।

अन्तर्ग्रस्त बाहरी पहलुओं सहित, राजनीतिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय समस्याओं से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुझाव दिए गए हैं । यह भी निर्णय लिया गया कि राजनीतिक स्तर पर बातचीत करना जारी रहेगा ताकि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को बहाल किया जा सके । बैठक में राज्य के सभी गुमराह हुए युवकों से पतन की राह पर ले जाने वाले हिंसा के रास्ते को त्यागने तथा राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में राजनीतिक मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया गया है।

पारित प्रस्ताव नीचे दिया गया है।

13 नवम्बर, 1991 को जम्मू और कश्मीर के राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक में पारित किया गया संकल्प

अनेक प्रमुख राजनैतिक व्यक्तियों और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए और प्रशिक्षित किए गए उग्रवादियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में लगातार की जा रही गतिविधियों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की, जिन गतिविधियों से राज्य के लोगों को व्यापक पीड़ा पहुंची, निर्दोष लोगों की जानें गईं, सम्पत्ति को नुकसान हुआ, वे आजीविका के साधनों से वंचित हुए, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां अस्त-व्यस्त हुईं, हजारों परिवारों को अपने घरों तथा गांवों को छोड़ना पड़ा, इस प्रकार से वह हमारे धर्म-निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक मूल्यों को गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

कश्मीर में धर्म-निरपेक्षवाद की शानदार प्रथाएं हैं । राज्य में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए । बैठक में देश की एकता और अखण्डता को उत्पन्न चुनौती का दृढ़ संकल्प से सामना करने के लिए लोगों और उनके प्रतिनिधियों के संकल्प को दोहराया गया। बैठक में जम्मू और कश्मीर पुलिस सहित सुरक्षा बलों द्वारा राज्य में अत्यन्त कठिन और दुर्गम परिस्थितियों में आतंकवाद का सामना करने के लिए उनकी प्रशंसा की गई तथा सुरक्षा बलों के उन सभी सदस्यों के परिवारों, प्रशासन तथा उन नागरिकों के प्रति शोक व्यक्त किया गया जिन्होंने इस संघर्ष में अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया ।

उग्रवाद और आतंकवाद से उत्पन्न खतरे का मुकाबला अधिक से अधिक लोगों को एक जुट करके ही किया जा सकता है । बैठक में जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों से इस कठिन समय में संगठित होने के लिए अपील की गई है ताकि शांति बहाल हो सके ।

अन्तर्ग्रस्त बाहरी पहलुओं सहित, राजनीतिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय समस्याओं से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुझाव दिए गए हैं । यह भी निर्णय लिया गया कि राजनीतिक स्तर पर बातचीत करना जारी रहेगा, ताकि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को बहाल किया जा सके । बैठक में राज्य के सभी गुमराह हुए युवकों से पतन की राह पर ले जाने वाले हिंसा के रास्ते को त्यागने तथा राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में राजनीकि मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया गया ।